(ग) सरकार इन मजदूरों की सेवाएं नियमित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी. एन. गाडगिल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) दिहाड़ी मजदूरों की सेवाओं का नियमित किया जाना उपयुक्त रिक्तियों की उपलब्धता और उनके द्वारा पात्रता की शर्तें पूरी करने पर निर्भर करता है । जैसे ही नियमित रिक्तियां उपलब्ध होती हैं, पात्र दिहाड़ी मजदूरों को खपाने के लिए कार्रवाई की जाती है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जाफराबाद में अधूरे मकानों का आवंटन

110. **श्री राम नरेश कुशवाहा** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मार्च, 1986 में लाटरी द्वारा लोगों को जाफराबाद में अधूरे मकान आवंटित किए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि जाफराबाद के मकानों का क्षेत्रफल कल्याणपुरी आदि जैसे अन्य स्थानों में स्थित मकानों से कम है;

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र के मकानों का क्षेत्रफल कितना है और इनका क्षेत्रफल अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम होने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन मकानों के निर्माण में घटिया किस्म की सामग्री का इस्तेमाल किया गया है; और

(ङ) क्या सरकार इस मामले की जांच करने तथा जाफराबाद में मकानों का आवंटन रोकने और इसके बजाय आवंटियों को अन्य स्थानों पर मकान देने का विचार रखती है ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इन फ्लैटों का ड्रा मार्च, 1986 में निकाला गया था । रिहायशी एकक अपूर्ण नहीं है । केवल उन मदों का आंशिक निष्पादन किया गया है जिन्हें वास्तविक रूप से कब्जा सौंपने के समय करना अपेक्षित होता है ।

(ख) और (ग) जाफराबाद में मकान निम्न आय वर्ग श्रेणी के हैं जिनका निर्माण न्यू पैटर्न स्कीम के अनुरूप किया गया है । स्वीकृत मानदण्डों के अनुसार निम्न आय वर्ग के मकानों का क्षेत्रफल 38 वर्गमीटर से 42 वर्गमीटर के भीतर होना चाहिए । जाफराबाद के मकानों का अच्छादित क्षेत्रफल सीढ़ियों के लिए क्षेत्रफल के भाग सहित 40.3 वर्ग मीटर प्रति एकक है । इसके अलावा, कल्याणपुरी के मकानों का निर्माण नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा किया गया था और दिल्ली प्रशासन द्वारा उनका उपयोग स्टाफ क्वार्टर्स के रूप में किया जा रहा है । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वहां केवल आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग श्रेणी के मकानों का निर्माण किया है । इस प्रकार जाफराबाद के निम्न आय वर्ग के फ्लैटों और कल्याणपुरी के मकानों/आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के मकानों में कोई तुलना नहीं है ।

(घ) मूल्य तकनीकी प्रतीक्षक (सी.टी.ई.) कोटि नियन्त्रण संगठन जिन्होंने रिहायशी एककों का निरीक्षण किया था, ऐसी कोई कमी नहीं बतायी थी ।

(ङ) जी, नहीं ।

Funds for urban developments

111. SHRI R. SAMBASIVA RAO: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that financial constraint is the biggest hurdle in urban development;

(b) whether Government propose to seek financial assistance from foreign agencies for this purpose; and

(c) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c) Seen in the context of enormity of urban problems resources available to the sector are not sufficient. This happens in all developing countries where demand for the resources is

high and supply not that happy. In the assessment of resources in the 7th Five Year Plan, account has been taken of the possible inflow of external assistance likely to be available for the plan as a whole. It is, however, not possible to precisely quantify at this stage the amount which would be available for urban development from out of these funds. To supplement the resources provided in the five year plans, a number of Urban Development projects are being implemented by the different State Governments, with the assistance of World Bank, UNICEF etc. The details are given in the enclosed statement.

STATEMENT

Details of World Bank and UNICEF assisted Urban Development Projects under implementation

Sl. No.	*Name of the Project*	*Quantum of World Bank Assistance*
		US $MILLION
1.	Calcutta Urban Development Project III	147
2.	Calcutta Urban Transport Project	56
3.	Madras Urban Development Project II	42
4.	Tamil Nadu Water Supply & Sanitation Project (Urban & Rural)	73
5.	Bombay Urban Transport Project	25
6.	Bombay Urban Development Project	105
7.	Bombay Water Supply & Sewerage Project (Urban Phase II)	196
8.	Kanpur Urban Development Project	25
9.	Madhya Pradesh Urban Development Project	24.1
10.	Gujarat Urban Development Project	62
11.	Gujarat Water Supply & Sewerage Project (Urban & Rural)	72
12.	Rajasthan Water Sypply & Swerage Project (Urban & Rural)	80
13.	Kerala Water Supply & Sanitation Project (Urban & Rural)	41

UNICEF ASSISTED SCHEME

UNICEF has agreed to provide US $ 9 2 Millions for the implementation of Urban Basic Services Scheme all over the country.